औद्योगिक गलियारों और एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने बनाया निवेश का माहौल

आर्थिक समीक्षा

इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण व अक्षय ऊर्जा में बढ़ा निवेश

04 हजार करोड़ इंसेंटिव का भुगतान पिछले वर्ष औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं के तहत हुआ

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यूपी का औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार बनकर उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश में तेज वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2025 में विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं के तहत करीब 4000 करोड़ का इंसेंटिव भुगतान किया गया। औद्योगिक गलियारों, एक्सप्रेसवे नेटवर्क व आधुनिक परियोजनाओं ने प्रदेश को उद्योगों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाया।

वर्ष 2016-17 में जहां प्रदेश में 14169 कारखाने पंजीकृत थे, वहीं वर्ष 2025-26 के नवंबर तक यह संख्या बढ़कर 30695 हो गई। राज्य के उद्योगों के सकल मूल्यवर्धन में गत वर्ष की तुलना में 25% की वृद्धि हुई है जो देश के प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2016-17 में जहां प्रदेश से कुल 84 हजार करोड़ का निर्यात हुआ था, वहीं वर्ष 2024–25 में यह 1.86 लाख करोड़ तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर तक 1.31 लाख करोड़ का निर्यात हो चुका है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में यूपी ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2022 में प्रदेश सातवें स्थान पर था। लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में प्रदेश इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा।

यूपी ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस मॉडल की ओर अग्रसर

दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूपी ने 2.94 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौते किए। भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट स्टार्ट अप ईकोसिस्टम रैंकिंग में यूपी टॉप परफॉर्मर कैटेगरी 'ए-1' में शामिल है। ओडीओपी योजना के तहत वर्ष 2018–19 से दिसंबर 2025 तक कुल 890.44 करोड़ की मार्जिन मनी दी गई। इससे 3.22 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। आर्थिक समीक्षा के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़ते हुए यूपी ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस मॉडल की ओर अग्रसर है। कंप्लायंस रिडक्शन में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।